समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करते है।
– अज्ञात

राय अपने–आप बदलती जाएगी

बहरहाल, अगर केंद्र सरकार मान रही है कि जम्मू–कश्मीर के हालात सुधर गए हैं तो सबसे पहले भारतीय संसद का एक प्रतिनिधि मंडल वहां हालात का जायजा लेने भेजा जाना चाहिए था।

अर्जुन राव।

एक और विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू–कश्मीर का दौरा कर लिया है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इस तरह का यह तीसरा दौरा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर दूसरा। ये दौरे वैश्विक स्तर पर जम्मू–कश्मीर को लेकर बनी धारणा को कितना बदल पाएंगे, कहना मुश्किल है। कश्मीर में हालात ज्यों–ज्यों सामान्य होते जाएंगे, दुनिया की राय अपने–आप बदलती जाएगी। जैसे पिछले दिनों यूरोपीय संघ ने इस मुद्दे पर होने वाला मतदान टाल दिया।

सरकार इस मामले में जितनी पारदर्शिता दिखाएगी, इससे जुड़ी धुंध उतनी ही साफ होगी। लेकिन, जिस तरह से विदेशी प्रतिनिधियों के दौरे कराए जा रहे हैं, उससे उलझन कम नहीं होने वाली। बुधवार को श्रीनगर पहुंचे 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में कनाडा, ऑस्ट्रिया, उज्बेकिस्तान,, फ्रांस, मैक्सिको, डेनमार्क, इटली, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, पोलैंड रवांडा आदि देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एक लैटिन अमेरिकी सांसद ने कहा कि वे केवल एक पर्यटक के तौर पर यहां आए हैं। अब इसे क्या कहा जाए?

यह साफ नहीं है कि ये प्रतिनिधि कश्मीर का जायजा लेने आए हैं या निजी सैर–सपाटे पर। अगर वे सचमुच राज्य के हालात का पता करने आए हैं, तो फिर यह कैसे जाना जाए कि उन्हें वहां खुलकर सबसे मिलने और हरेक पहलू को जानने का मौका मिला? एक प्रतिनिधि ने यह कहकर भ्रम बढ़ा दिया कि वहां उन्हें सभी स्कूल खुले दिखे, जबकि सचाई यह है कि 16 दिसंबर से घाटी के स्कूलों में जाड़े की छुट्टियां चल रही हैं, जो तीन महीने चलती हैं। स्थितियां बदली हैं, लेकिन इतनी नहीं।

जम्मू–कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा कई अन्य नेता पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत नजरबंद हैं। बहरहाल, अगर केंद्र सरकार मान रही है कि जम्मू–कश्मीर के हालात सुधर गए हैं तो सबसे पहले भारतीय संसद का एक प्रतिनिधि मंडल वहां हालात का जायजा लेने भेजा जाना चाहिए था। राज्य के मौजूदा हालात को लेकर उनकी राय को देश की जनता ज्यादा गंभीरता से लेती और आश्वस्त होती। बाकी दुनिया में भी इसका सकारात्मक संदेश जाता। एक परिपक्व लोकतंत्र में अपने जन प्रतिनिधियों को दरकिनार कर विदेशी सांसदों को तवज्जो देना एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की हैसियत पर सवाल खड़े करता है। अक्टूबर में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल आया था, तब विपक्ष के अलावा देश के कई राजनेताओं–विश्लेषकों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। उसके बाद सरकार ने अपने मंत्रियों को वहां भेज दिया। यह सही है कि कुछ देश कश्मीर मामले में हमें घेर रहे हैं पर उन्हें जवाब तभी दिया जा सकेगा जब घाटी को लेकर हमारा रवैया कुछ छुपाने जैसा न नजर आए। कश्मीर को लेकर सारी उलझनों को दूर करने का अभी बस एक ही तरीका है कि संसद का एक प्रतिनिधिमंडल वहां के सघन दौरे पर भेजा जाए।

चेतना पर ध्यान

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

जब सब कुछ सहज तरीके से चल रहा हो... जीवन बिना व्यवधान आगे बढ़ रहा हो तब अपने भीतर चेतना का भाव जागृत करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। यह आपके भीतर और आसपास ऊर्जा के उस प्रवाह को उत्पन्न करता है जिसकी आवृत्ति काफी ज्यादा है। इस ऊर्जा क्षेत्र में अचौतन्य, हिंसा, किसी प्रकार का मनमुटाव.... प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही वह उस क्षेत्र के भीतर पनप सकते हैं।

जब आप अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनने लगते हैं.. . जो कि आपके वर्तमान का एक जरूरी हिस्सा है... तब आप यह जानकर काफी हैरान होंगे कि आपकी पृष्ठभूमि स्थिर है... वह गतिशील नहीं है... आप अंदरूनी तौर पर पूरी तरह सहज हैं।

संपादकीय

भाषा और छवि

बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस को अपने वैचारिक आधार का निर्माण करना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही उसे एक परिपक्व, सूझबूझ वाला, संयत और संतुलित भाषा का प्रयोग करने वाला नेतृत्व भी तैयार करना होगा। राहुल और प्रियंका, दोनों में नेतृत्व के ये अवयव बिल्कुल नहीं हैं। चुनावों में दूसरों की जीत और बीजेपी की पराजय से कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला। क्षेत्रीय पार्टियों की कृपा पर आखिर वह कब तक चलेगी? दिल्ली चुनाव प्रचार में ही उन्होंने कहा कि 'ये जो नरेन्दर मोदी है न, छः महीने सात–आठ महीने बाद अपने घर से नहीं निकलेगा। नौजवान इसे डंडा मारेंगे।' इस तरह की अपमानजनक भाषा का संदेश यह निकलता है कि मोदी के बढ़े हुए कद को कमजोर न कर पाने से वे इतने तिलमिला गए हैं कि अपने शब्दों तक पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया है। भाषा और हाव–भाव से ही जनमानस में नेता की छवि निर्मित होती है। मोदी पर आक्रमण होते ही बीजेपी यह बताना शुरू कर देती है कि देखो ये हमारा किस तरह अपमान कर रहे हैं। इससे राहुल गांधी की स्वयं की छवि एक अपरिपक्व, राजनीति की अंतर्धारा को न समझने वाले तथा सतही सोच वाले व्यक्ति जैसी बनती है।

केजरीवाल ने चुनाव के कई महीने पहले से मोदी की निंदा तो दूर, उनका नाम लेना तक बंद कर दिया था। हिंदुत्व, सेक्युलरवाद, सांप्रदायिकता आदि पर कोई बात ही नहीं की। इससे भी कांग्रेस कुछ सीखे तो शायद वह भविष्य में बीजेपी के खिलाफ बेहतर रणनीति बना सकती है।

केंद्र व सभी राज्यों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी की यह दुर्दशा भी उसके नेतृत्व को नए सिरे से पार्टी खड़ी करने के लिए प्रेरित नहीं करती।

हाशिये की पार्टी बन गई कांग्रेस

अवधेश कुमार।।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर अपना खाता नहीं खोल पाई। लेकिन पार्टी के नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि वे यहां बीजेपी के सत्ता में नहीं आ पाने से ही संतुष्ट हैं। यह सही है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी झारखंड में पराजित हुई और और हरियाणा में जोड़–तोड़ करके सरकार बना पाई। दिल्ली में जहां वह सरकार बनाने की उम्मीद कर रही थी, वहीं सीटों के मामले में वह हाशिये की पार्टी बन गई। यह स्थिति बीजेपी के लिए निस्संदेह चिंताजनक है और विपक्ष इससे भविष्य के चुनावों को लेकर बेहतर उम्मीद बांध सकता है। मगर कांग्रेस की उम्मीदें साकार होने की संभावना तो तभी बन सकती है जब वह स्वयं अपने दम पर बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में रहेगी।

कहने को कांग्रेस कह सकती है कि आज महाराष्ट्र और झारखंड में वह सत्ता में है। हरियाणा में भी उसने ठीक–ठाक प्रदर्शन किया। लेकिन इन प्रदेशों में उसकी हैसियत क्या है? महाराष्ट्र में शिवसेना ने परिणाम के बाद मुख्यमंत्री पद की जिद नहीं की होती या बीजेपी ने उसकी मांग स्वीकार कर ली होती तो वहां कांग्रेस सत्ता में कैसे आती? झारखंड में भी वह मुख्य पार्टी

थी। बीजेपी का प्रवेश बाद में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां था अवश्य, लेकिन वह कभी मुख्य शक्ति नहीं था। आज कांग्रेस वहां शासन में है लेकिन जेएमएम की बदौलत दूसरे स्तर की भूमिका में। उसे जो सीटें मिलीं उसमें जेएमएम, आरजेडी और बीजेपी के विद्रोहियों और असंतुष्टों की बड़ी भूमिका थी। इतने सब के बाद भी कांग्रेस को वहां केवल 13.8 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। यानी महाराष्ट्र की तरह वहां भी कांग्रेस सिमट चुकी है। कांग्रेस के साथ जेएमएम और आरजेडी के मत मिला दीजिए तो वह बीजेपी के 33.4 प्रतिशत के बराबर होता है।

आज की तारीख में कांग्रेस का प्रभावी जनाधार केवल नौ राज्यों में बचा है। देश के ज्यादातर राज्यों में वह समाप्तप्राय है। जरा नजर डालिए– दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस खत्म है। केरल में भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। इनमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां उसका शासन है। केंद्र व सभी राज्यों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी की यह दुर्दशा भी उसके नेतृत्व को नए सिरे से पार्टी खड़ी करने के लिए प्रेरित नहीं करती तो फिर इसके बेहतर भविष्य की कामना कोई कैसे कर सकता है?

इस पर बहस हो सकती है कि राहुल गांधी द्वारा उस चुनाव में टीवी कैमरों के साथ मंदिर–मंदिर जाना, अपने को शुद्ध हिंदू और शिवभक्त बताना कांग्रेस की वैचारिक पृष्ठभूमि के लिहाज से सही था या गलत, पर इस रणनीति ने कांग्रेस को वहां टक्कर में ला दिया और बीजेपी को नाकों चने चबाने पड़े। लेकिन उसके बाद उन्होंने 'चौकीदार चोर है' का नारा लगाना आरंभ किया। प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेसी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे, जिसकी प्रतिक्रिया लोकसभा चुनाव में साफ देखने को मिली।

अष्टयोग- 4955

3	1					
	31		37		28	
4		5			1	2
	29		40	7	34	3
1	6			3		
	32		26	5	34	1
	5		3		2	7

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4954 का हल

1	2	3	4	5	6	7
7	24	2	32	3	41	6
2	3	4	5	6	7	1
6	28	1	36	2	30	4
3	4	5	6	7	1	2
5	39	7	43	4	25	5
4	5	6	7	1	2	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

एक और तर्क पेश किया जा रहा है

मोहन। महिलाओं को कमांड रोल न देने के सपोर्ट में एक और तर्क पेश किया जा रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन को युद्धबंदी बना लिया गया, सोचिए अगर उनकी जगह कोई महिला होती तो? कहीं रेप हो गया तो? दरअसल यह तर्क कम कुतर्क ज्यादा है। यह वही सोच है कि महिलाओं को रात में अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कहीं किसी ने छेड़ दिया तो? जहां तक युद्धबंदी होने पर रेप की बात है तो वह किसी पुरुष के साथ भी हो सकता है। पुरुष के साथ हुए दुराचार को हम आसानी से भूल जाते हैं जबकि महिला के साथ हुए उसी अपराध को कभी परिवार, कभी समाज और कभी देश की इज्जत का सवाल बना डालते हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि युद्धबंदी के साथ व्यवहार के कुछ नियम होते हैं। एक यह तर्क भी दिया जा रहा है कि कॉम्बैट (युद्ध) सैनिकों के लिए स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे होते हैं जबकि महिलाओं के लिए कम। निश्चित रूप से किसी खास रोल के लिए स्टैंडर्ड तय किए जा सकते हैं।